



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

5/11/90

भाग II—खंड 3—उप-खंड (II)
PART II—Section 3—Sub-Section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 518]
No. 518]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 19, 1989/श्रावण 28, 1911
NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 19, 1989/SRAVANA 28, 1911

इस भाग में निम्न खंड संलग्न की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रचा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(वैकिंग प्रभाग)
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1989

का. प्रा. 652 (प्र).—केन्द्रीय सरकार, बैंककारी
विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा
45 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन भारतीय
रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने के
पश्चात् बैंक ऑफ थंजावूर लिमिटेड की बाबत 19 अगस्त,
1989 को कार्रवार की ममाप्ति से तारीख 19 दिसम्बर,
1989 तक जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है, की कालावधि
के लिए अधिस्थगन आदेश करती है और अधिस्थगन की
कालावधि के दौरान उस बैंककारी कंपनी के विरुद्ध

सभी कार्यवाहियों और कार्यवाहियों के प्रारम्भ करने या
चालू रखने को इस शर्त के अधीन रहते हुए, स्थगित करती
है कि ऐसे स्थगन से उक्त अधिनियम की धारा 35
की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार
द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर या उक्त अधिनियम की धारा
38 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसकी शक्तियों
के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. केन्द्रीय सरकार यह भी निवेश देती है कि बैंक ऑफ
थंजावूर लिमिटेड को मंजूर की गयी अधिस्थगन की काला-
वधि के दौरान, वह बैंक भारतीय रिजर्व की लिखित
अनुशंसा के बिना;

(क) अपने दायित्वों और बाध्यताओं के निर्वहन में
या अन्यथा कोई उधार या अग्रिम नहीं देगा,
कोई दायित्व उत्पन्न नहीं करेगा, कोई विनिधान
नहीं करेगा, या किसी संघाय के लिए कदार या
उसका संवितरण नहीं करेगा या इसमें इसके

पश्चात् उपबंधित विस्तार और रीति के सिवाए कोई समझौता या ठहराव नहीं करेगा :

- (1) प्रत्येक बचत या चालू खाते में या किसी अन्य निक्षेप में चाहे वह किसी भी नाम ज्ञात हो, कुल अतिशेष के 50 प्रतिशत से अधिक राशि परन्तु यह तब तक कि किसी एक व्यक्ति के नाम में (और किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में नहीं) जमा खाते की बाबत संवत्त रकम की कुल धनराशि व्यक्तियों के मामले में 10,000 रुपये तथा संस्थानों के मामले में 25,000 रुपये से अधिक नहीं है, परन्तु यह और कि ऐसी कोई रकम ऐसे किसी निक्षेपकर्ता संस्था को जो किसी रूप में बैंक का ऋणी है, संदत्त नहीं की जाएगी।
- (2) उक्त बैंक द्वारा जारी किए गए कोई ड्राफ्ट या संदाय आदेशों की कोई रकम और जो उस तारीख को जिसकी अधि-स्थगन प्रवृत्त होता है, असंवत्त रह जाती है;
- (3) तारीख 19 अगस्त, 1989 को या उससे पूर्व संग्रहण के लिए प्राप्त और उस तारीख के पूर्व को या उसके पश्चात् वसूल किए गए बिलों की रकम;
- (4) कोई ऐसा व्यय जो उक्त बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध फाइल किए गए किसी वाद या अपील के संबंध में या बैंक द्वारा अधि-प्राप्त डिब्री के संबंध में या उसको देय किसी रकम को वसूल करने के लिए आवश्यक रूप से उपगत किया जाना है, परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक वाद या अपील या डिब्री या कार्यवाही की बाबत व्यय 2500 रुपये से अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा इसके उपगत किए जाने से पूर्व अधिप्राप्त की जाएगी; और
- (5) किसी अन्य मद पर कोई अन्य व्यय जहां तक वह बैंककारी कम्पनी के प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन करने के लिये बैंककारी कम्पनी की राय में आवश्यक है, परन्तु जहां किसी मद पर कुल व्यय, अधिस्थगन के आदेश के पूर्व छः कैलेंडर मास के दौरान उस मद के मददे औसत मासिक व्यय से अधिक है या जहां उक्त अधि के दौरान उस मद के मददे कोई व्यय उपगत नहीं हुआ है, और ऐसे में मद पर व्यय 2,500 रुपये

से अधिक है वहां भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा अतिरिक्त व्यय उपगत किए जाने के पूर्व अधिप्राप्ति की जाएगी।

- (ख) तारीख 19 अगस्त, 1989 को कारबार की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा किए गए करार के अनुमरण के सिवाए, अपनी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय अंतर या उसका अन्यथा व्ययन नहीं करेगा।

3. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि बैंक आफ थंजावूर लिमिटेड उसे मंजूर की गयी स्थगन की काला-वधि के दौरान निम्नलिखित और संदाय अर्थात् बैंक ऑफ थंजावूर लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इसके किसी समनुपंगी या किसी अन्य बैंक द्वारा बैंक आफ थंजावूर लिमिटेड को सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध उधारों/अग्रियों के या दिए गए प्रतिदार के लिए आवश्यक है, और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होता है, असंवत्त है अतिरिक्त संदाय कर सकता है।

4. केन्द्रीय सरकार, यह और निदेश देती है कि अधि-स्थगन की कालावधि के दौरान बैंक आफ थंजावूर लिमिटेड पूर्वोक्त संदाय करने के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक किसी अन्य बैंक के पास अपना खाता चलाने के लिए अनुज्ञात होगी, परन्तु इस आदेश की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य पूर्वोक्त बैंक से अपना यह समाधान करने की अपेक्षा करती है कि इस आदेश द्वारा अधिरोपित शर्तों का थंजावूर बैंक लिमिटेड के पक्ष में कोई रकम जारी किए जाने से पूर्व पालन किया जा रहा है।

5. केन्द्रीय सरकार यह और निदेश देती है कि बैंक आफ थंजावूर लिमिटेड अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, ऐसे किन्हीं बिलों को, जिनकी वसूली नहीं हुई है, उसको प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए अनुरोध पर उस दिशा में वापस लौटा सकेगा यदि बैंक का ऐसे बिलों में कोई अधिकार या हक या हित नहीं है।

6. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि बैंक आफ थंजावूर लिमिटेड ऐसे माल या प्रतिभूतियों को निम्न-लिखित रीति में और विस्तार तक निर्मुक्त या परिदत्त कर सकेगा जो किसी उधार, नकद प्रत्यय या ओवरड्राफ्ट के लिए इसके पास गिरवी रखा गया है, आडमानित, विलंगमित या बंधक या अन्यथा प्रभारित किया गया है :—

- (1) किसी ऐसी दशा में जिसमें, यथास्थिति, उधार लेने वाले या उधार देने वालों से देय सभी रकमों के मद्दे पूर्व संदाय बैंक द्वारा बिना शर्त के प्राप्त कर लिया गया है; और

- (2) किसी अन्य दशा में, अनुबंधित अनुपातों या ऐसे अनुपातों से जो अधिस्थगन आदेश के प्रवृत्त होने से पूर्व रखे गए थे, इन दोनों में से जो भी उच्चतर हो, नीचे उक्त माल या प्रतिभूतियों पर सीमाओं के अनुपात को कम किए बिना ऐसी मात्रा तक जो आवश्यक या सम्भव हो।

[सं. 17/5/89-बी.ओ. III]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 19th August, 1989

S.O. 652 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, (10 of 1949) the Central Government, after considering an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of that section, hereby makes an order of Moratorium in respect of the Bank of THANJAVUR LTD. for the period from the close of business on the 19th August, 1989 upto and inclusive of the 19th December, 1989 and hereby stays the commencement or continuance of all actions and proceedings against that banking company during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Central Government of its powers under clause (b) of sub-section (4) of section 35 of the said Act or the exercise by the Reserve Bank of India of its powers under section 38 of the said Act.

2. The Central Government hereby also directs that during the period of moratorium granted to it, the Bank of THANJAVUR LTD. shall not, without the permission in writing of the Reserve Bank of India, —

- (a) Grant any loan or advance, incur any liability, make any investment or agree to or disburse any payment, whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except to the extent and in the manner provided hereunder :

- (i) A sum not exceeding 50 per cent of the total balance in every savings bank or current account or in any other deposit by whatever name called, provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 10,000 and in the case of institutions Rs. 25,000 and provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the bank in any way :

- (ii) the amounts of any drafts or pay orders issued by the said bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;

- (iii) the amounts of the bills received or collection on or before the 19th August 1989 and realised before, on or after that date;

- (iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against or decrees obtained by the Said Bank or for realising any amounts due to it, provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree or proceeding in excess of Rs. 2500 the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before it is incurred; and

- (v) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the banking company necessary for carrying on the day-to-day administration of the banking company, provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or if no expenditure has been incurred on account of that item in the past exceeds a sum of Rs. 2500 the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the additional expenditure is incurred;

- (b) sell, transfer or otherwise dispose of any of its immovable properties except in pursuance of any agreement entered into by it prior to the close of business on the 19th August, 1989.

3. The Central Government hereby also directs that the Bank of THANJAVUR LTD. may, during the period of the moratorium granted to it, make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government securities or other securities, to the Bank of THANJAVUR LTD., by the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force.

4. The Central Government hereby further directs that during the period of moratorium the Bank of THANJAVUR LTD., shall be permitted to operate its accounts with the Reserve Bank of India or with any other bank for the purposes of making the payments aforesaid, provided that nothing in this order shall be deemed to require the Reserve Bank of India or any other bank aforesaid to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Bank of THANJAVUR LTD.

5. The Central Government hereby further directs that the Bank of THANJAVUR LTD., may, during the period of moratorium, return any bills which have remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the bank has a right to title to, or interest in, such bills.

6. The Central Government hereby also directs that the Bank of THANJAVUR LTD., may, release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or over draft —

- (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the bank, unconditionally; and
- (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[No. 17/5/89-BO-III]

का.आ. 653 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अज्ञेयन पत्र विचार करने पश्चात् पारर सेंट्रल बैंक लिमिटेड की बाबत 19 अगस्त, 1989 को कारबार की समाप्ति से तारीख 19 सितम्बर, 1989 तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, की कालावधि के लिए आधिस्थगन आदेश करती है और आधिस्थगन की कालावधि के दौरान उस बैंककारी कम्पनी के विरुद्ध सभी कार्यवाहियों और कार्यवाहियों के प्रारम्भ करने या चालू रखने की इस शर्त के अधीन रहते हुए स्थगित करती है कि ऐसे स्थगन से उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर या उक्त अधिनियम की धारा 38 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि पारर सेंट्रल बैंक लिमिटेड को मंजूर की गयी आधिस्थगन की कालावधि के दौरान, यह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा के बिना—

- (क) अपने दायित्वों और बाध्यताओं के निर्बहण में या अन्यथा कोई उधार या अधिम नहीं देगा, कोई दायित्व उपगत नहीं करेगा, कोई विनिधान नहीं करेगा, या किसी संदाय के लिए करार या उसका संवितरण नहीं करेगा या इसमें उसके

पश्चात उपबध्द विस्तार और रीति के सिवाए कोई समझौता या हस्ताक्षर नहीं करेगा।

- (1) प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते में या किसी अन्य निक्षेप में चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हों, कुल अतिमेष के 50 प्रतिशत से अनधिक राशि परन्तु यह तब जब कि किसी एक व्यक्ति के नाम में (और किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयोजित रूप में नहीं) जमा खाते की बाबत संश्लेष रकम की कुल धनराशि व्यक्तियों के मामले में 10,000 रुपये तथा संस्थाओं के मामले में 25,000 रुपये से अधिक नहीं है, परन्तु यह और कि ऐसी कोई रकम ऐसे किसी निक्षेपकर्ता संस्था को जो किसी रूप में बैंक का ऋणी है, संदत्त नहीं की जाएगी
- (2) उक्त बैंक द्वारा जारी किए गए कोई ब्राफ्ट या संदाय आदेशों की कोई रकम और जो उस तारीख को जिसका अधिस्थगन प्रवृत्त होता है, असंदत्त रह जाती है ;
- (3) तारीख 19 अगस्त, 1989 को या उससे पूर्व संग्रहण के लिए प्राप्त और उस तारीख के पूर्व को या उसके पश्चात वसूल किए गए बिलों की रकम ;
- (4) कोई ऐसा व्यय उक्त बैंक द्वारा या उसके अधिकार क्षेत्र में किए गए किसी तद या अपील के संबंध में या बैंक द्वारा अभिप्राप्त डिक्ली के संबंध में या उसकी लिये किसी रकम को वसूल करने के लिए आवश्यक रूप से उपयुक्त किया जाना है, परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक वाद या अपील या डिक्ली या कार्यवाही की बाबत व्यय 2,500 रुपये से अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक को लिखित अनुज्ञा इसके उपगत किए जाने से पूर्व अभिप्राप्त की जाएगी ; और
- (5) किसी अन्य पद पर कोई अन्य व्यय जहां तक वह बैंककारी कम्पनी के प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन करने के लिए बैंककारी कम्पनी की राय में आवश्यक है, परन्तु जहां किसी पद पर कुल वार आधिस्थगन के आदेश के पूर्व छः कैलेंडर मास के दौरान उस मद के मद्दे अंशतः मासिक व्यय से अधिक है या जहां उक्त अवधि के दौरान उस मद के मद्दे कोई व्यय उपगत नहीं हुआ

है और ऐसे में मद पर व्यय 2500 रुपये से अधिक है वहां भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा अतिरिक्त व्यय उपगत किए जाने के पूर्व अभिप्राति की जाएगी।

- (ख) तारीख 19 अगस्त, 1989 को कारबार की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा किए गए करार के अनुसरण के सिवाए अपनी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय अंतरण या उसका अन्यथा व्ययन नहीं करेगा।

3. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि पारुर सैन्ट्रल बैंक लिमिटेड उसे मंजूर की गई स्थगन की कालावधि के दौरान विम्नलिखित और संदाय, अर्थात् पारुर सैन्ट्रल लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इसके किसी समन्युपंगी या किसी अन्य बैंक द्वारा पारुर सैन्ट्रल बैंक लिमिटेड को सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध उधारों/अग्रिमों के या दिए गए प्रतिशोध के लिए आवश्यक है और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होता है, असदत्त है अतिरिक्त संदाय कर सकता है।

4. केन्द्रीय सरकार, यह और निदेश देती है कि अधिस्थगन की कालावधि के दौरान पारुर सैन्ट्रल बैंक लिमिटेड पूर्वोक्त संदाय करने के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक किसी अन्य बैंक के पास अपना खाता चलाने के लिए अनुज्ञात होगी, परन्तु इस आदेश की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य पूर्वोक्त बैंक से अपना यह समाधान करने की अपेक्षा करती है कि इस आदेश द्वारा अधिरूपित मामलों का पारुर सैन्ट्रल बैंक लिमिटेड के पक्ष में कोई रकम जारी किए जाने से पूर्व पालन किया जा रहा है।

5. केन्द्रीय सरकार यह और निदेश देती है कि पारुर सैन्ट्रल बैंक लिमिटेड अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, ऐसे किन्हीं बिलों को, जिनकी वसूली नहीं हुई है, उसको प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए अनुरोध पर उस दिशा में वापस लौटा सकेगा यदि बैंक का ऐसे बिलों में कोई अधिकार या हक या हित नहीं है।

6. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि पारुर सैन्ट्रल बैंक लिमिटेड ऐसे माल या प्रतिभूतियों को निम्नलिखित रीति में और विस्तार तक निमुक्त या परिशुद्ध कर सकेगा जो किसी उधार मकद प्रत्यय या ओवर-ड्राफ्ट के लिए इसके पास गिरवी रखा गया है,

आवृत्तानित, विलगमित या बंधक या अन्यथा प्रभारित किया गया है :—

- (1) किसी ऐसी दशा में जिसमें, यथास्थिति, उधार लेने वाले या उधार लेने वालों से देय सभी रकमों के मुद्दे पूर्ण संदाय बैंक द्वारा बिना शर्त के प्राप्त कर लिया गया है; और
- (2) किसी अन्य दशा में, अनुवर्जित अनुपातों या ऐसे अनुपातों से जो अधिस्थगन आदेश के प्रवृत्त होने से पूर्व रखे गये थे, इन दोनों में जो भी उच्चतर हो, नोचे उक्त माल या प्रतिभूतियों पर सोमाओं के अनुपात का कम किए बिना ऐसी मात्रा तक जा आवश्यक या संभव हो।

[सं. 17/7/89-वां अं-III(i)]

S.O. 653(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, (10 of 1949), the Central Government, after considering an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of that section, hereby makes an order of moratorium in respect of the PARUR CENTRAL BANK LTD, for the period from the close of business on the 19th August, 1989 upto and inclusive of the 19th December, 1989 and hereby stays the commencement or continuance of all actions and proceedings against that banking company during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Central Government of its powers under clause (b) of sub-section (4) of section 35 of the said Act or the exercise by the Reserve Bank of India of its powers under section 38 of the said Act.

2. The Central Government hereby also directs that during the period of moratorium granted to it, the PARUR CENTRAL BANK LTD., shall not, without the permission in writing of the Reserve Bank of India,—

- (a) Grant any loan or advance, incur any liability, make any investment or agree to or disburse any payment, whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except to the extent and in the manner provided hereunder.

- (i) A sum not exceeding 50 per cent of the total balance in every savings bank or current account or in any other deposit by whatever name called, provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 10,000/- and in the case of institutions Rs. 25,000/- and provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the bank in any way;

- (ii) the amounts of any drafts or pay orders issued by the said bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;
- (iii) the amounts of the bills received for collection on or before the 19th August 1989 and realised before, on or after that date;
- (iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against or decrees obtained by the said bank or for realising any amounts due to it, provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree or proceeding is in excess of Rs. 2500/- the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before it is incurred; and
- (v) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the banking company necessary for carrying on the day-to-day administration of the banking company, provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or if no expenditure has been incurred on account of that item in the past exceeds a sum of Rs. 2500/-, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the additional expenditure is incurred;
- (b) sell, transfer or otherwise dispose of any of its immovable properties except in pursuance of any agreement entered into by it prior to the close of business on the 19th August, 1989.

3. The Central Government hereby also directs that the PARUR CENTRAL BANK LTD. may, during the period of the moratorium granted to it, make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government securities or other securities, to the PARUR CENTRAL BANK LTD. by the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force.

4. The Central Government hereby further directs that during the period of moratorium the PARUR CENTRAL BANK LTD. shall be permitted to operate its accounts with the Reserve Bank of India or with any other bank for the purposes of making the payments aforesaid, provided that nothing in this order shall be deemed to require the Reserve Bank of India or any other bank aforesaid to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the PARUR CENTRAL BANK LTD.

5. The Central Government hereby further directs that the PARUR CENTRAL BANK LTD. may, during the period of moratorium, return any bills which have remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the bank has no right or title to, or interest in, such bills.

6. The Central Government hereby also directs that the PARUR CENTRAL BANK LTD., may, release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit overdraft —

- (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the bank, unconditionally; and
- (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[No. 17/89-80-III(i)]

अधिपूचना

का. आ. 654 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात् पूर्वावक्त बैंक लिमिटेड की बाबत 19 अगस्त, को कारबार की समाप्ति से तारीख 19 दिसम्बर, 1989 तक जिनके अन्तर्गत यह तारीख भी है, की कालावधि के लिए अधिव्ययन आदेश करती है और अधिव्ययन की कालावधि के दौरान उस बैंककारी कम्पनी के विरुद्ध सभी कार्यवाहियों और कार्यवाहियों के प्रारम्भ करने या चालू रखने को इस शर्त के अधीन रखने द्वारा स्थगित करती है कि ऐसे स्वयं से उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर या उक्त अधिनियम की धारा 38 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिबन्धन प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. केन्द्रीय सरकार यह भी निर्देश देती है कि पूर्वावक्त बैंक लिमिटेड को मंजूर की गयी अधिव्ययन का कालावधि के दौरान, यह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा के बिना —

- (क) अपने दायित्वों और बाधकताओं से निर्वहन में या अन्यथा कोई उधार या अग्रिम नहीं देगा,

कोई दायित्व उपगत नहीं करेगा, कोई विनिधान नहीं करेगा, या किसी संदाय के लिये करार या उसका संवितरण नहीं करेगा या इसमें इसके पश्चात् उपबंधित विस्तार और रीति के सिवाए कोई समझौता या ठहराव नहीं करेगा:—

- (1) प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते में या किसी अन्य निक्षेप में चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, कुल अतिशेष के 50 प्रतिशत से अनधि राशि परन्तु यह तब जब कि किसी एक व्यक्ति के नाम में (और किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में नहीं) जमा खाते की की बाबत संबन्धित रकम की कुल धनराशि व्यक्तियों के मामले में 10,000 रुपये तथा संस्थाओं के मामले में 25,000 रुपये से अधिक नहीं है, परन्तु यह और कि ऐसी कोई रकम ऐ से किसी निक्षेपकर्ता संस्था को जो किसी रूप में बैंक का ऋणी है, संबन्ध नहीं की जाएगी;
- (2) उक्त बैंक द्वारा जारी किए गए कोई ड्राफ्ट या संवाय की कोई रकम और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन प्रवृत्त होता है, असदत्त रह जाती है;
- (3) तारीख 19 अगस्त, 1989 को या उससे पूर्व संग्रहण के लिये प्राप्त और उस तारीख से पूर्व को या उसके पश्चात् वसूल किए गए बिलों की रकम;
- (4) कोई ऐसा व्यय जो बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध फाइल किए गए किसी बाब या अपील के संबंध में या उक्त बैंक द्वारा अभिप्राप्त डिक्ली के संबंध में या उसकी देय किसी रकम को वसूल करने के लिए आवश्यक रूप से उपगत किया जाना है, परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक बाब या अपील या डिक्ली या कार्यवाही की बाबत व्यय 2,500 रुपये से अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा इसके उपगत किए जाने से पूर्व अधिप्राप्त की जाएगी; और
- (5) किसी अन्य मद्द पर कोई अन्य व्यय जहां तक वह बैंककारी के प्रतिष्ठित के प्रशासन का संचालन करने के लिए बैंककारी कम्पनी की राय में आवश्यक है, परन्तु अहां किसी मद्द

पर कुल व्यय, अधिस्थगन के आदेश के के पूर्व छः कैलेंडर मास के दौरान उस मद्द के मद्दे औसत मासिक व्यय से अधिक है या जहां उक्त अधि के दौरान उस मद्द के मद्दे कोई अन्य उपगत नहीं हुआ है, और ऐसे में मद्द पर व्यय 2,500 रुपये से अधिक है वहां भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा अतिरिक्त व्यय उपगत किए जाने के पूर्व अभिप्राप्त की जाएगी।

(ख) तारीख 19 अगस्त, 1989 को कारबार की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा किए गए करार के अनुसरण के सिवाए अपनी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, अंतरण या उसका अन्यथा व्ययन नहीं करेगा।

3. केन्द्रीय सरकार सरकार यह भी निदेश देती है कि पूर्वांचल बैंक लिमिटेड उसे मंजूर की गयी स्थगन की कालावधि के दौरान निम्नलिखित और संवाय, अर्थात् पूर्वांचल बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इसके किसी समनुषगी या किसी अन्य बैंक द्वारा पूर्वांचल बैंक लिमिटेड को सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध उधारों/अधिमों के या दिए गए प्रतिदाय के लिये आवश्यक है और जो उस तारीख को जिसको अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होता है, असदत्त है अतिरिक्त संवाय करसकता है।

4. केन्द्रीय सरकार, यह और निदेश देती है कि अधिस्थगन की कालावधि के दौरान पूर्वांचल बैंक लिमिटेड पूर्वांचल संवाय करने के प्रयोजन के लिये भारतीय रिजर्व बैंक किसी अन्य बैंक के पास अपना खाता, चलाने के लिये अनुज्ञात होगी परन्तु इस आदेश की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य पूर्वांचल बैंक से अपना यह समाधान करने की अपेक्षा करती है कि इस आदेश द्वारा अधिरोपित शर्तों का पूर्वांचल बैंक लिमिटेड के पक्ष में कोई रकम जारी किए जाने से पूर्व पालन किया जा रहा है।

5. केन्द्रीय सरकार यह और निदेश देती है कि पूर्वांचल बैंक लिमिटेड अधिस्थगन की कालावधि के दौरान, ऐसे किन्हीं बिलों को जिनकी वसूली नहीं हुई है, उसको प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए अनुरोध पर उस दिशा में वापस लौटा सकेगा यदि बैंक का ऐसे बिलों में कोई अधिकार या हक या हित नहीं है।

6. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि पूर्वाञ्चल बैंक लिमिटेड ऐसे माल या प्रतिभूतियों को निर्धारित रीति में और वितार तक निर्मुक्त या परिदत्त कर सकेगा जो किसी उधार, नकद प्रत्यय या ओवरड्राफ्ट के लिए इसके पास गिरवी रखा गया है आडमानित, बिलग मित या बंधक या अन्यथा प्रभारित किया गया है—

- (1) किसी ऐसी दशा में जिसमें यथास्थिति, उधार लेने वाले या उधार लेने वालों से देय नगो रकमों के मद्दे पूर्ण संदाय बैंक द्वारा बिना शर्त के प्राप्त कर लिया गया है ; और
- (2) किसी अन्य दशा में अनुबंधित अनुपातों या ऐसे अनुपातों से जो अधिस्थगन आदेश के प्रवृत्त होने से पूर्व रखे गए थे, इन दोनों में से जो भी उच्चतर हो नीचे उक्त माल या प्रतिभूतियों पर सीमाओं के अनुपात को कम किए बिना ऐसी मात्रा तक जो आवश्यक या संभव हो ।

[स. 17 / 7/89 बी ओ. III (ii)]

S.O. 654(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, (10 of 1949) the Central Government, after considering an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of that section, hereby makes an order of moratorium in respect of the PURBANCHAL BANK LTD. for the period from the close of business on the 19th August, 1989 upto and inclusive of the 19th December, 1989 and hereby stays the commencement or continuance of all actions and proceedings against that banking company during the period of moratorium, subject to the conditions that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Central Government of its powers under clause (b) of sub-section (4) of section 35 of the said Act or the exercise by the Reserve Bank of India of its powers under section 38 of the said Act.

2. The Central Government hereby also directs that during the period of moratorium granted to it, the PURBANCHAL BANK LTD. shall not, without the permission in writing of the Reserve Bank of India,—

- (a) Grant any loan or advance, incur any liability, make any investment or agree to or disburse any payment, whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except to the extent and in the manner provided hereunder :
- (i) A sum not exceeding 50 per cent of the total balance in every savings bank or current account or in any other deposit by whatever name called, provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the

name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 10,000 and in the case of institutions Rs. 25,000 and provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the bank in any way;

- (ii) the amounts of any drafts or pay orders issued by the said bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force ;
- (iii) the amounts of the bills received for collection on or before the 19th August, 1989 and realised before, on or after that date :
- (iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against or decrees obtained by the said bank or for realising any amounts due to it, provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree or proceeding is in excess of Rs. 2500 the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before it is incurred; and
- (v) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the banking company necessary for carrying on the day-to-day administration of the banking company, provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that item during the six calendar months preceding the order of moratorium, or if no expenditure has been incurred on account of that item in the past exceeds a sum of Rs. 2500 the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the additional expenditure is incurred;
- (b) sell, transfer or otherwise dispose of any of its immovable properties except in pursuance of any agreement entered into by it prior to the close of business on the 19th August, 1989.

3. The Central Government hereby also directs that the PURBANCHAL BANK LTD. may, during the period of the moratorium granted to it, make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government securities or other securities, to the PURBANCHAL BANK LTD. by the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force.

4. The Central Government hereby further directs that during the period of moratorium the PURBANCHAL BANK LTD. shall be permitted to operate its accounts with the Reserve Bank of India or with

any other bank for the purposes of making the payments aforesaid, provided that nothing in this order shall be deemed to require the Reserve Bank of India or any other bank aforesaid to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the PURBANCHAL BANK LTD.

5. The Central Government hereby further directs that the PURBANCHAL BANK LTD. may during the period of moratorium, return any bills which have remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the bank has no right or title to, or interest in, such bills.

6. The Central Government hereby also directs that the PURBANCHAL BANK LTD. may, release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft :—

- (i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the Bank, unconditionally; and
- (ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[No. 17/7/89-80-III(ii)]

का. आ. 655(अ).—केन्द्रीय सरकार बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1649 का 10) की धारा 45 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस धारा की उपधारा (1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करने के पश्चात् बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड की बाबत 19 अगस्त 1989 को कारबार की समाप्ति से तारीख 19 दिसम्बर 1989 तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है की कालावधि के लिये अधिस्थगन आदेश करती है और अधिस्थगन की कालावधि के दौरान उस बैंककारी कम्पनी के विरुद्ध सभी कार्यवाहियों और कार्यवाहियों के प्रारम्भ करने या चालू रखने की इस शर्त के अधीन रहते हुए स्थगित करती है कि ऐसे स्थगन से उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर या उक्त अधिनियम की धारा 38 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसकी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड को मंजूर की गयी अधिस्थगन की कालावधि के दौरान वह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा के बिना —

- (क) अपने दायित्वों और बाध्याओं के निर्वहन में या अन्यथा कोई उधार या अग्रिम नहीं

देगा, कोई दायित्व उपगत नहीं करेगा, कोई विनिधान नहीं करेगा, या किसी संदाय के लिए करार या उसका संवितरण नहीं करेगा या इसमें इसके पश्चात् उपबंधित विस्तार और रोलि के सिवाए कोई समझौता या ठहराव नहीं करेगा :—

- (1) प्रत्येक बचत बैंक या चालू खाते में या किसी अन्य निक्षेप में नादे वह किसी भी नाम से जात हो, कुल अतिशेष के 50 प्रतिशत से अनधिक राशि परन्तु यह तब जब कि किसी एक व्यक्ति के नाम में (और किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में नहीं) जमा खाते की बचत संदत्त रकम की कुल धनराशि व्यक्तियों के मामले में 10,000 रुपये तथा संस्थाओं के मामले में 25,000 रुपये से अधिक नहीं है, परन्तु यह और कि ऐसी कोई रकम ऐसे किसी निक्षेपकर्ता संस्था को जो किसी रूप में बैंक का ऋणी है, संदत्त नहीं की जाएगी।
- (2) उक्त बैंक द्वारा जारी किए गए कोई ड्राफ्ट या संदाय आदेशों की कोई रकम और जो उस तारीख को जिस को अधिस्थगन प्रवृत्त होता है, असंदत्त रह जाती है ;
- (3) तारीख 19 अगस्त, 1989 को या उससे पूर्व संग्रहण के लिए प्राप्त और उस तारीख के पूर्व को या उसके पश्चात् वसूल किए गए बिलों की रकम ;
- (4) कोई ऐसा व्यय जो उक्त बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध फाईल किए गए किसी वाद या अपील के संबंध में या बैंक द्वारा अभिप्राप्त डिक्ली के संबंध में या उसको देय किसी रकम को वसूल करने के लिए आवश्यक रूप से उपगत किया जाना है, परन्तु यदि ऐसे प्रत्येक वाद या अपील डिक्ली या कार्यवाही की बाबत व्यय 2500 रु. से अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा इसके उपगत किए जाने से पूर्व अभिप्राप्त की जाएगी; और
- (5) किसी अन्य मद पर कोई अन्य व्यय जहां तक बैंककारी कम्पनी के प्रति दिन के प्रशासन का संचालन करने के लिए बैंककारी कम्पनी की राय में आवश्यक है, परन्तु जहां किसी मद पर कुल व्यय, अधिस्थगन के आदेश के पूर्व छः कैलेंडर मास के दौरान उस मद के मद्दे औसत मासिक व्यय से अधिक है या जहां उक्त अवधि के दौरान उस मद के मद्दे कोई व्यय उपगत नहीं हुआ है, और ऐसे में मद पर व्यय 2500 रुपये से

अधिक है वह भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित अनुज्ञा अतिरिक्त व्यय उपगत किए जाने के पूर्व अभिप्राप्त की जाएगी।

- (ख) तारीख 19 अगस्त, 1989 को कारबार की समाप्ति से पूर्व उसके द्वारा किए गए करार के अनुसरण के सिवाय अपनी स्थावर सम्पत्ति का विक्रय अंतरण या उसका अन्यथा व्ययन नहीं करेगा।

3. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड उसे मंजूर की गयी स्थगन की कालावधि के दौरान निम्नलिखित और संदाय, अर्थात्:— बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या इसके किसी समनुषंगी या किसी अन्य बैंक द्वारा बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड की सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध उधारों/अग्रिमों के या दिए गए प्रतिदाय के लिए आवश्यक है, और जो उस तारीख को जिसकी अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होता है, असंवेत है, अतिरिक्त संदाय कर सकता है।

4. केन्द्रीय सरकार, यह और निदेश देती है कि अधिस्थगन की कालावधि के दौरान बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड पूर्वीकृत संदाय करने के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक किसी अन्य बैंक के पास अपना खाता चलाने के लिए अनुज्ञात होगी, परन्तु इस आदेश को किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य पूर्वीकृत बैंक में अपना यह समाधान करने की अपेक्षा करती है कि इस आदेश द्वारा अधिरोपित शर्तों का बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड के पक्ष में कोई रकम जारी किए जाने से पूर्व पालन किया जा रहा है।

5. केन्द्रीय सरकार यह और निदेश देती है कि बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड अधिस्थगन की कालावधि के दौरान ऐसे किन्हीं बिलों को जिनकी वसूली नहीं हुई है, उसको प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए अनुरोध पर उस दिशा में वापस लौटा सकेगा यदि बैंक का ऐसे बिलों में कोई अधिकार या हक या हित नहीं है।

6. केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि बैंक आफ तमिलनाडु लिमिटेड ऐसे माल या प्रतिभूतियों को निम्नलिखित शर्तों में और बिस्तार तक नमूक्त या परिदत्त कर सकेगा जो किसी उधार नकद प्रत्यय या ओवर ड्राफ्ट के लिए, इसके पास गिरवी रखा गया है, आडमानित विलगमित या बंधक या अन्यथा प्रभारित किया गया है:—

- (1) किसी ऐसी दशा में जिसमें यथाम्बिति, उधार लेने वाले या उधार देने वालों से देय सभी रकमों के मद्दे पूर्ण संदाय बैंक द्वारा

बिना शर्त के प्राप्त कर लिया गया है; और

- (2) किसी अन्य दशा में, अनुबंधित अनुपातों या ऐसे अनुपातों से जो अधिस्थगन आदेश प्रवृत्त होने से पूर्व रखे गए थे इन दोनों में के जो भी उच्चतर हो, तोचे उक्त माल या प्रतिभूतियों पर सीमाओं के अनुपात को कम किए किए बिना ऐसी मात्रा तक जो आवश्यक या संभव हो

[सं. 17/7/89—बी आ III (iii)]

मन्त्रेवर झा, संयुक्त सचिव

S.O. 655 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949, (10 of 1949) the Central Government, after considering an application made by the Reserve Bank of India under Sub-Section (1) of that section, hereby makes an order of moratorium in respect of the Bank of TAMILNAD LTD., for the period from the close of business on the 19th August, 1989 upto and inclusive of the 19th December, 1989 and hereby stays the commencement or continuance of all actions and proceedings against that banking company during the period of moratorium, subject to the condition that such stay shall not in any manner prejudice the exercise by the Central Government of its powers under clause (b) of sub-section (4) of section 35 of the said Act or the exercise by the Reserve Bank of India of its powers under section 38 of the said Act.

2. The Central Government hereby also directs that during the period of moratorium granted to it, the Bank of TAMILNAD LTD., shall not, without the permission in writing of the Reserve Bank of India,—

- (a) Grant any loan or advance, incur any liability, make any investment or agree to or disburse any payment, whether in discharge of its liabilities and obligations or otherwise, or enter into any compromise or arrangement, except to the extent and in the manner provided hereunder :

- (i) A sum not exceeding 50 per cent of the total balance in every savings bank or current account or in any other deposit by whatever name called, provided that the sum total of the amounts paid in respect of the accounts standing in the name of any one person (and not jointly with that of any other person) does not exceed Rs. 10,000/- and in the case of institutions Rs. 25,000/- and provided further that no amount shall be paid to any depositor who is indebted to the bank in any way;

- (ii) the amounts of any drafts or pay orders issued by the said bank and remaining

unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force;

(iii) the amounts of the bills received for collection on or before the 19th August, 1989 and realised before, on or after that date;

(iv) any expenditure which has necessarily to be incurred in connection with any suits or appeals filed by or against or decrees obtained by the said bank or for realising any amounts due to it, provided that if the expenditure in respect of each such suit or appeal or decree or proceedings is in excess of Rs. 2500 the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before it is incurred; and

(v) any expenditure on any other item in so far as it is in the opinion of the banking company necessary for carrying on the day-to-day administration of the banking company, provided that where the total expenditure on any item in any calendar month exceeds the average monthly expenditure on account of that is on during the six calendar months preceding the order of moratorium, or if no expenditure has been incurred on account of that item in the past exceeds a sum of Rs. 2500, the permission in writing of the Reserve Bank of India shall be obtained before the additional expenditure is incurred;

(b) Sell, transfer or otherwise dispose of any of its immovable properties except in pursuance of any agreement entered into by it prior to the close of business on the 19th August, 1989.

3. The Central Government hereby also directs that the Bank of TAMILNAD LTD. may, during the period of the moratorium granted to it, make the following further payments, namely, the amounts necessary for repaying loans or advances granted against Government Securities or other securities, to

the Bank of TAMILNAD LTD. by the Reserve Bank of India or the State Bank of India or any of its subsidiaries or by any other bank and remaining unpaid on the date on which the order of moratorium comes into force.

4. The Central Government hereby further directs that during the period of moratorium the Bank of TAMILNADU LTD., shall be permitted to operate its accounts with the Reserve Bank of India or with any other bank for the purposes of making the payments aforesaid, provided that nothing in this order shall be deemed to require the Reserve Bank of India or any other bank aforesaid to satisfy itself that the conditions imposed by this order are being observed before any amounts are released in favour of the Bank of TAMILNAD LTD.

5. The Central Government hereby further directs the period of moratorium, return any bills which have remained unrealised to the persons entitled to receive them on a request being made in this behalf by such persons, if the bank has no right or title to, or interest in, such bills.

6. The Central Government hereby also directs that the Bank of TAMILNAD LTD., may, release or deliver goods or securities which have been pledged, hypothecated or mortgaged or otherwise charged to it against any loan, cash credit or overdraft —

(i) in any case in which full payment towards all the amounts due from the borrower or borrowers, as the case may be, has been received by the bank, unconditionally; and

(ii) in any other case, to such an extent as may be necessary or possible, without reducing the proportions of the margins on the said goods or securities below the stipulated proportions or the proportions which were maintained before the order of moratorium came into force, whichever may be higher.

[No. 17/7/89-BO-III(iii)]
MANTRESHWAR JHA, Jt. Secy.

